राजस्थान घुमन्तु जाति कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष 18.50 लाख रू. की रिश्वत लेते गिरफ्तार

एसीबी ने पिछले दो दिन में जयपुर और सीकर में कार्रवाई कर पूर्व अध्यक्ष केसावत सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया

जयपुर, 15 जुलाई (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) की टीम ने पिछले दो दिनों में सीकर और जयपुर में कार्रवाई करते हुये राजस्थान घुमन्तु जाति कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत, अनिल कुमार धरेन्द्र, ब्रह्मप्रकाश, रविन्द्र शर्मा को 18 लाख 50 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

- **आरोपियों ने आर.पी.एस.सी. की अधिशासी अधिकारी भर्ती परीक्षा में पास करवाने व ओ.एम.आर. शीट बदलवाने के लिए 25 लाख रुपए में सौदा किया था।**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी चल रही है।**

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को राजगढ़ निवासी परिवादी ने शिकायत दी थी। शिकायकर्ता ने ए.सी.बी. को बताया कि, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अधिशासी अधिकारी (ई.ओ.) भर्ती परीक्षा में पास करवाने तथा ओ.एम.आर. शीट बदलवाने के नाम पर राज्य घुमन्तु जाति कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत तथा तीन प्राइवेट व्यक्ति अनिल कुमार धरेन्द्र, ब्रह्मप्रकाश, रविन्द्र शर्मा 40 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं।

इस पर ए.सी.बी., जयपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक कालूराम रावत के सुपरवीजन में ए.सी.बी. सीकर इकाई के पुलिस उपाधीक्षक राजेश जांगिड़ के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। इस दौरान आरोपियों द्वारा 25 लाख रुपये रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इस पर ए.सी.बी. की टीम ने शुक्रवार को सीकर में अनिल कुमार धरेन्द्र पुत्र सत्यनारायण निवासी हनुमानगढ़ टाउन एवं ब्रह्मप्रकाश पुत्र देवदा शर्मा निवासी दिल्ली को परिवादी से 18 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ए.सी.बी. ने मामले और लोगों के लिप्त होने के मद्देनजर इस पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखा। पूछताछ में सामने आया कि, यह रकम आगे जयपुर जानी है। उसी दिन देर रात एक बजे सीकर में रविन्द्र शर्मा पुत्र बलराम निवासी टिब्बी, हनुमानगढ़ को हाईवे पर 7 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। वहीं इनसे पूछताछ के बाद शनिवार को जयपुर में आरोपी राज्य घुमन्तु जाति कल्याण बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत पुत्र हरचंदा निवासी कुंभा मार्ग, प्रतापनगर, जयपुर को परिवादी से 7 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया।

ए.सी.बी. के पुलिस महानिरीक्षक सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। प्रारम्भिक पूछताछ में पता चला कि आरोपियों में एक जयपुर सचिवालय का रिटायर्ड कर्मचारी है।

ए.सी.बी की टीम ने 18.5 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में राजस्थान घुमंतु जाति कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

क्या आपको कम सुनाई देता है।?
ऑटोमेटिक कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
कॉकलियर इम्पलांट, ऑटिजम
डिले स्पीच, हकलाना, तुतलाना
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
सम्पर्क- 94602 07080

भारत और यू.ए.ई. अब अपनी मुद्रा, रुपया और दिरहम में आपसी कारोबार करेंगे

प्र.मंत्री मोदी व यू.ए.ई. के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी मुद्रा में कारोबार करने पर पूर्ण सहमति बनी

नई दिल्ली, 15 जुलाई। प्रधानमंत्री मोदी के युनाइटेड अरब अमारेट्स (यू.ए.ई.) के दौरे पर कई अहम डील हुई हैं। इनमें कारोबारी लेन-देन अपनी मुद्राओं में शुरू करने और भारत की एकीकृत भुगतान प्रणाली यू.पी.आई. को यू.ए.ई. के तत्काल भुगतान मंच आई.पी.पी. से जोड़ने पर शनिवार को सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यहां यू.ए.ई. के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ हुई व्यापक बातचीत के दौरान इन दोनों मुद्दों पर सहमति जताई गई। इसके अलावा आई.आई.टी. दिल्ली का एक कैंपस अबू धाबी में खोलने के बारे में भी समझौता हुआ है।

- **इसके अलावा, आई.आई.टी. दिल्ली का एक कैम्पस अबू धाबी में खोलने के बारे में भी समझौता हुआ है।**
- **बैठक खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, भारत और यू.ए.ई. के बीच व्यापार, पिछले साल मई में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता लागू होने के बाद से करीब 20 प्रतिशत बढ़ चुका है।**

बैठक खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और यू.ए.ई. के बीच व्यापार पिछले साल मई में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता लागू होने के बाद से करीब 20 प्रतिशत बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि भारत और यू.ए.ई. के बीच स्थानीय मुद्राओं में कारोबारी लेन-देन शुरू करने का समझौता दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग और आपसी विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से द्विपक्षीय कारोबार एवं निवेश को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलना हमेशा खुशी की बात है। विकास के लिए उनकी ऊर्जा और दृष्टिकोण सराहनीय है। हमने सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों सहित भारत-यू.ए.ई. संबंधों से जुड़े सभी विषयों पर चर्चा की।

मोदी ने कहा कि उन्हें शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से हमेशा भाई का प्यार मिला। उन्होंने यू.ए.ई. के राष्ट्रपति से कहा कि जिस तरह से हमारे देशों के बीच संबंधों का विस्तार हुआ है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। भारत का हर व्यक्ति आपको एक सच्चे दोस्त के रूप में देखता है। दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच हुए समझौते के तहत दोनों देशों की मुद्राओं रुपये और यू.ए.ई. दिरहम में कारोबारी लेन-देन किए जा सकेंगे।

इस समझौते पर भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के गवर्नर शक्तिकांत दास और यू.ए.ई. सेंट्रल बैंक के गवर्नर खालेद मोहम्मद बलामा ने दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। आधिकारिक वक्तव्य के मुताबिक, दोनों देशों के केंद्रीय बैंक रुपये और दिरहम का कारोबारी लेन-देन में इस्तेमाल बढ़ाने के लिए एक ढांचा खड़ा करेंगे।

इसके साथ ही वे दोनों देशों की भुगतान प्रणालियों यू.पी.आई. और आई.पी.पी. को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए सहयोग करेंगे। इससे भारतीय रुपये और यू.ए.ई. दिरहम दोनों को लाभ होगा। आर.बी.आई. ने एक बयान में कहा कि समझौता ज्ञापन में चालू खातों के सारे लेन-देन और स्वीकृत पूंजी खाता लेन-देन भी शामिल हैं।

489 दिन जेल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है कि लड़के की माँ एवं मामा की मौजूदगी में एक मंदिर में उनकी शादी हो गई थी तथा वे पति-पत्नी के रुप में रहने लगे थे। लेकिन, उसके बाद प्रेम में कटुता आ गई। लड़के पर प्रीवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेज (पी.ओ.सी.एस.ओ.- पोक्सो) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपहरण एवं बलात्कार के आरोप लगाये गये हैं।

उसे एक वयस्क के रुप में 489 दिन जेल में रखा गया तथा बाद में 242 दिन से अधिक समय तक किशोर अपराधी गृह में रखा गया। शुक्रवार (14 जुलाई) को सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी करीब दो साल की कड़ी परीक्षा की समाप्त कर दी तथा उसे जमानत दे दी। यह जमानत ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित उचित शर्तों के तहत दी गई है। उसके परिवार ने एक सत्र न्यायालय में एक अर्जी लगाकर अनुरोध किया था कि उसे बाल-निरीक्षण गृह में रखा जाये। अन्त में, करीब एक साल बाद अदालत ने उसे किशोर अपराधी गृह में भेज दिया था। इस जगह वह करीब 8 महीने रहा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तथा एक हाई कोर्ट ने उसकी रिहाई के लिये उसके परिवार द्वारा किये गये प्रयासों पर पानी फेर दिया था।

अन्त में यह लड़का, एडवोकेट नमित सक्सेना के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसने इस साल अप्रैल में इस लड़के का क्रिमिनल रिविजन पिटिशन खारिज कर दी थी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और सुधांशू धूलिया की बैंच ने शुक्रवार को उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

राहुल ने मानहानि ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के तुरन्त बाद, 24 मार्च, 2023 को उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गांधी की सजा पर "स्टे" मिलने से उन्हें लोकसभा सांसद के रूप में उनकी बहाली का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन उन्हें न तो सत्र न्यायालय से कोई राहत मिली है और न गुजरात उच्च न्यायालय से। राहुल गांधी के खिलाफ कुल 10 केस विचाराधीन हैं। उनके खिलाफ पुणे की अदालत में वीर सावरकर के पौत्र ने भी एक केस दायर कर रखा है। यह केस राहुल गांधी द्वारा इंग्लैंड के केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वीर सावरकर के लिये प्रयुक्त शब्दों को लेकर किया गया है।

लड़ाकू विमानों के इंजन व स्कॉर्पिन पनडुब्बियां बनाने में मदद देगा फ्रांस

पेरिस, 15 जुलाई (वार्ता)। भारत और फ्रांस ने अपनी रणनीतिक साझीदारी की 25वीं वर्षगांठ पर अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को अभूतपूर्व ऊंचाई देते हुए लड़ाकू विमानों के इंजन, स्कॉर्पीन पनडुब्बी एवं भारी मालवाहक हेलीकॉप्टर के इंजन के विकास एवं सह-उत्पादन के करार करने के साथ ही एक दीर्घकालिक रक्षा औद्योगिक सहयोग का रोडमैप बनाने की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फ्रांस की ऐतिहासिक यात्रा के संपन्न होने पर दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझीदारी को अगले 25 वर्षों तक विस्तार देने के रोडमैप क्षितिज 2047: भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ, भारत-फ्रांस संबंधों की एक सदी की ओर से यह घोषणा की गयी। इस संयुक्त दस्तावेज में कहा गया है कि भारत-फ्रांस साझीदारी की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर दोनों देश 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने के लिए एक रोडमैप अपनाने पर सहमत हुए, जो भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की शताब्दी और रणनीतिक साझीदारी की स्वर्ण जयंती वर्ष का जश्न मनाएगा।

- **फ्रांस लड़ाकू विमानों व हैलिकॉप्टरों के इंजन बनाने की टैक्नॉलजी भारत के साथ साझा करने व भारत में ही इनके निर्माण के लिए समग्र मदद करने के लिए तैयार हुआ।**
- **प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक फ्रांस यात्रा सम्पन्न होने से पहले भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर आपसी संबंधों का, अगले 25 वर्षों का विज़न पेश किया।**

भारत और फ्रांस अन्तर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के हित में एक साथ काम करने का इरादा रखते हैं और भारत-प्रशांत और उससे आगे एक नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। वे अपने-अपने संप्रभु और रणनीतिक हितों के अनुरूप, समान लोगों के बीच साझेदारी के ढांचे के भीतर काम करने के लिए सहमत हैं, जैसा उन्होंने 1998 से किया है।

इस संयुक्त दस्तावेज में 'सुरक्षा और संप्रभुता के लिए साझीदारी: संप्रभु रक्षा क्षमताओं का साझा निर्माण' विषय में सामरिक सहयोग को रेखांकित किया गया है। दस्तावेज में कहा गया, भारत में आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक एवं तकनीकी आधार विकसित करने में फ्रांस भारत के प्रमुख भागीदारों में से एक है। भारत और फ्रांस तीसरे देशों के लाभ सहित उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के सह-विकास और सह-उत्पादन में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

दस्तावेज में कहा गया कि पांच दशकों से अधिक समय से सैन्य उड्डयन में अपने उत्कृष्ट सहयोग के अनुरूप, भारत और फ्रांस भारत द्वारा ऑर्डर किए गए 36 राफेल की समय पर डिलीवरी का स्वागत करते हैं। भविष्य में, भारत और फ्रांस लड़ाकू विमान इंजन को संयुक्त रूप से विकसित करके उन्नत वैधानिक प्रौद्योगिकियों में अपने रक्षा सहयोग का अभूतपूर्व विस्तार करेंगे। दोनों पक्ष भारतीय मल्टीरोल हेलीकॉप्टर (आई.एम.आर.एच.) कार्यक्रम के तहत भारी-लिफ्ट हेलीकॉप्टरों में मोटर लगाने के लिए सफ्रान हेलीकॉप्टर इंजन, फ्रांस के साथ औद्योगिक सहयोग के पक्षधर हैं। आई.एम.आर.एच. कार्यक्रम में इंजन विकास के लिए, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) और सफ्रान हेलीकॉप्टर इंजन, फ्रांस के बीच साझीदारी का एक समझौता संपन्न हुआ है।दस्तावेज के अनुसार आपसी विश्वास पर आधारित इस रक्षा औद्योगिक साझीदारी के अन्य उदाहरणों में शक्ति इंजन के लिए फोर्जिंग और कास्टिंग की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए भी सफ्रान हेलीकॉप्टर इंजन और एच.ए.एल. के बीच अनुबंध हुआ है।

अभिषेक बच्चन लोकसभा चुनाव लड़ेंगे?

नई दिल्ली, 15 जुलाई। बॉलीवुड अभिनेता और सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन को लेकर प्रयागराज में अचानक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।

ये चर्चाएं उनकी अगली पारी को लेकर हैं। कहा जा रहा है अभिषेक 2024 के चुनावी रण में प्रयागराज की धरती पर ताल ठोंक सकते हैं।

याद दिला दें कि 1984 में अमिताभ बच्चन ने भी इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में अमिताभ ने पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हराकर इतिहास रच दिया था।

विपक्ष की बैंगलोर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से गढी गई कुमार की छवि का पूरा पूरा लाभ लिया जाये। बिहार महागठबन्धन के नेताओं का कहना है कि उनके राजनीति प्रभाव में थोडी बहुत कमी आ जाने के बावजूद, नीतीश कुमार, भाजपा नेताओं की कार्यशैली की बेहतर समझ रखने के कारण, भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सर्वाधिक उपयोगी नेता के रूप में हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पूर्वी क्षेत्र में रीजनल कोऑर्डिनेटर और दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की जिम्मेदारी दी जा सकती हैं।

एजेंडा में अगले वर्ष आम चुनावों में भाजपा के सामने एक साझा उम्मीदवार खड़ा करने की रणनीति का ब्लूप्रिन्ट तैयार करना भी शामिल है।

अगर यह योजना बन गई तो इससे सबसे ज्यादा कांग्रेस को फायदा होगा क्योंकि 188 सीटों पर भाजपा का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है। वर्ष 2019 में विपक्ष के वोट बंटने की वजह से भाजपा ने इन सीटों पर कांग्रेस का हरा दिया था।

वन-टू-वन रणनीति का पहला टैस्ट करने के लिए कांग्रेस नेता राजस्थान मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ के विधान सभा चुनावों में यह नीति लागू करने पर जोर दे सकते हैं, जहां कांग्रेस भाजपा में सीधी टक्कर हैं।

पटना सम्मेलन की तुलना में इस सम्मेलन में के.डी.एम.के. तथा एम.डी.एम.के. सहित 8 अन्य क्षेत्रीय दलों को भी निमंत्रण दिया गया है।

ये दोनों पार्टियां वर्ष 2014 में एन.डी.ए. मं थी। बैंगलूर सम्मेलन में सोनिया गाधी की मौजूदगी से विपक्षी एकता को बल मिलेगा क्योंकि उनके विपक्ष के कई नेताओं से सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध हैं।

हाइटैंशन लाइन की चपेट में आए कांवड़िये, 5 की मौत

मेरठ, 15 जुलाई। यू.पी. के मेरठ में भावनपुर के राली चौहान गांव में शनिवार रात करीब 8.30 बजे दर्दनाक हादसे से कोहराम मच गया। कांवड़ और उसके साथ चल रहा साउंड सिस्टम 11 हजार के.वी. की बिजली लाइन की चपेट में आ गया और उसमें सवार तमाम लोग करंट से झुलस गए। 20 घायलों को आनन-फानन में आसपास के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज भेजा गया। हादसे में दो भाइयों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर ए.डी.जी., आईजी और डीएम-एस.एस.पी. भी मौके पर पहुँचे। वहीं, इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर हंगामा करते हुए जाम लगा दिया और बिजली विभाग के कर्मचारियों पर मुकदमे की मांग की। राली चौहान गांव निवासी संजू और प्रदीप अपने साथियों के साथ शनिवार रात कांवड़ लेकर हरिद्वार से गांव पहुंचे। गांव से बाहर मेरठ-किला मार्ग पर कांवड़ देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा थी।

मोदी शासनकाल में इसरो के मिशनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई

मोदी के कार्यकाल में 47 मिशन लॉन्च हो चुके हैं तथा मनमोहन सिंह सरकार में 24 मिशन लॉन्च हुये थे

नई दिल्ली, 15 जुलाई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) ने शुक्रवार (14 जुलाई) को श्रीहरिकोटा से एल.वी.एम.3-एम 4 रॉकेट के जरिए अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 23 अगस्त को अगर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत इसे हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसके साथ ही मोदी सरकार के नाम एक और नया रिकॉर्ड होगा।

मोदी सरकार की बात करें तो इसरो ने इस सरकार में अब 47 मिशनों को लॉन्च किया है। इसकी तुलना में इसरो ने मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान 24, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान छह और पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार के दौरान पांच मिशन को लॉन्च किया था। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में काफी प्रगति की है।

- **अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान छः और पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार के दौरान पांच मिशन लॉन्च हुए थे। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि, मोदी सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में काफी प्रगति की है।**

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में जवाहरलाल नेहरू सरकार द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना के साथ शुरू किया गया था, जो सात साल बाद इंदिरा गांधी शासन के दौरान इसरो बन गया। पिछले नौ वर्षों की बात करें तो इसरो द्वारा किए गए 47 लॉन्च मिशनों में से केवल तीन उपग्रह अपनी कक्षाओं में स्थापित नहीं होने में विफल रहे। जबकि 22 जुलाई, 2019 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 मिशन ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी और चंद्रमा के चारों ओर एक ऑर्बिटर स्थापित किया, लेकिन यह चंद्रमा की सतह पर नरम लैंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। अंतरिक्ष मिशनों की गति में तेजी का श्रेय अंतरिक्ष विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री, जितेंद्र सिंह मोदी सरकार को दिया है उन्होंने कहा है कि, मोदी सरकार ने अंतिरक्ष मिशन को लेकर अधिक संसाधन और एक मजबूत नीति, परिवेश प्रदान किया।

'चुनाव पंचायत का था...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बड़ी भूमिका की खातिर, कुछ लोगों के शव कोई मायने नहीं रखते हैं। इन ग्रामीण चुनावों में अब तक करीब 50 लोगों की बलि दी जा चुकी है और यह संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। अब भी, जबकि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, पूरे राज्य से लोगों के मरने तथा उनकी हत्याओं की रिपोर्ट आ रही हैं। अपनी जीत को पार्टी की निर्णायक जीत के रुप में प्रस्तुत करते हुये, वे विपक्षी दलों के विजेताओं पर अपनी पार्टी छोड़कर, तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिये दबाव बना रही हैं। बहुत से क्षेत्रों में, जीते हुये उम्मीदवारों तथा उनके परिवारों पर अपनी पार्टियाँ छोड़ने के लिये जबरदस्त दबाव डाला जा रहा है।

ऐसी रिपोर्ट चर्चा में हैं कि अन्य पार्टियों के विजेता उम्मीदवारों को तृणमूल में शामिल होने के लिये भारी-भरकम धनराशि की पेशकश की जा रही है। यही नहीं, भाजपा के कुछ पदाधिकारियों तक को रिश्वत दी जा रही है कि वे अपने लोगों का तृणमूल कांग्रेस में लायें। विपक्षी दलों के कुछ विजयी उम्मीदवार तो तृणमूल गाड़ी में सवार भी हो गये हैं।

एक मामला तो ऐसा बताया जा रहा है कि विजयी उम्मीदवार के बेटे का अपहरण कर लिया गया था। वह विजयी उम्मीदवार, जो किसी विपक्षी दल के सदस्य के रुप में मतगणना कक्ष के अंदर गया था, तृणमूल के विजेता के रुप में बाहर निकला था। विपक्षी दल अब अपने विजयी उम्मीदवारों को ऐसे सुरक्षित मकानों में रखने के लिये कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जहाँ तक तृणमूल के कर्ताधर्ताओं के लम्बे हाथ नहीं पहुंच सकें।

ममता बनर्जी के व्यक्तित्व के कुछ मजबूत पक्ष भी हैं। वे दुर्दमनीय हैं तथा प्रतिकूल परिस्थिति में संघर्ष करना उन्हें प्रिय है। वे राष्ट्रीय राजनीति में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिये संघर्षरत रहेंगी। राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाना उनकी भूल एलं अपरिवर्तनीय आकांक्षा है। लेकिन क्या उनकी कोशिश सफल होगी?

दुष्कर्म व हत्या...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बैठा रहा। पिता के कहने पर बच्ची शोरूम के नल से पानी लेने चली गई तो किशोर भी वहां से निकल गया। काफी देर तक जब बच्ची वापस नहीं आई तो उसकी माँ उसे ढूंढने लगी, लेकिन वो नहीं मिली। इस दौरान किशोर भी वहां आ गया और बोला कि, बच्ची को बाड़ा बाड़ा में देखकर आओ। जब परिजनों ने वहां जाकर देखा तो बच्ची को निर्वस्त्र अवस्था में मृत पाया। उसका गला कटा हुआ था। बच्ची के पिता ने आमेर थाने में किशोर पर शक जाहिर करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई।

जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किशोर को निरुद्ध कर उसकी मानसिक व शारीरिक क्षमता की जांच करने के बाद बाल न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया। बाद में बाल न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों की परिधि में उसका वयस्क की तरह ट्रायल करने के लिए मामला सामान्य कोर्ट में भेज दिया। जहां अदालत ने किशोर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

राहुल गांधी ने एक बार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बराबर करने के लिए अमेरिका से यूरोप तक विदेशी शक्तियों की ओर झुक रहे हैं और भारत के हितों का नाश करने वाले वैश्विक सिंडीकेटों से मिले हुए हैं।

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राफेल मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले निपटा दिया था और राहुल को संवैधानिक संस्थाओं पर शक जताना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल ने कुछ गलत टिप्पणी के लिए सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें जिम्मेवार रहने को कहा मगर वे और जिम्मेवारी साथ-साथ नहीं चल सकते।

भाटिया ने कहा, "यह शर्मनाक है कि जब प्रधानमंत्री का फ्रांस में सम्मान हो रहा है तो कुछ लोग छाती पीट रहे हैं।

भाजपा आई.टी. विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने हमला जारी रखते हुए यूरोपीय संसद की टिप्पणियों को राहुल की मणिपुर यात्रा से जोड़ा और कहा, "यह संयोग नहीं हो सकता कि राहुल की मणिपुर यात्रा के बाद ही यूरोपीय संसद ने मणिपुर हिंसा पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर चर्चा का प्रस्ताव रखा।" मालवीय ने राहुल पर आरोप लगाया कि वे मणिपुर के दुर्भाग्यपूर्ण विवाद का राजनीतिकरण कर रहे हैं।

मालवीय ने कहा, "यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी घरेलू राजनैतिक हिसाब बराबर के लिए अमेरिका से यूरोप तक विदेशी शक्तियों का साहरा ले रहे हैं। वे भारत के रणनीतिक और भौगोलिक-राजनैतिक हितों को नुकसान पहुंचाने वाले वैश्विक सिंडीकेटों से मिले हुए हैं।

कांग्रेस के हमले की कमान जयराम रमेश ने संभाली, जिन्होंने मणिपुर मामले पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, जनवरी 1977 में येल विश्वविद्यालय के विख्यात अर्थशास्त्री रिचर्ड नैल्सन ने एक प्रभावशाली लेख "द मून एण्ड द घेटो" प्रकाशित किया था जो छात्रों में बहुत लोकप्रिय हुआ। नैल्सन प्रश्न करते हैं कि तकनीकी रूप से अति सक्षम अमेरिका चंद्रमा पर इंसान भेज देता है लेकिन अपनी घरेलू समस्याएं हल नहीं कर सकता, विशेषकर भीतरी शहरों में। यह एक बहुत विचारणीय विश्लेषण हैं जिसका हमसे भी संबंध है।

रमेश ने कहा, "हम चांद पर जा सकते हैं लेकिन देश में लोगों की समस्याएं हल करने के इच्छुक नहीं हैं। नैल्सन के लेख का भारतीय संस्करण हो सकता है द मून एंड मणिपुर।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने स्मृति ईरानी पर वार करते हुए कहा, "मंत्री स्मृति ईरानी से कहा कि वे इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बुलवाएं। प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में घूम रहे हैं लेकिन मणिपुर पर एक मिनट भी बात नहीं करते।

गूगल का अनुमान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिए जाएंगे।

लेकिन यह गठबंधन विवाद रहित नहीं है। इन "इन्फ्लुएंसर्स" की सार्वजनिक संवाद की घटिया संस्कृति है कि सरकार के साथ इनके गठबंधन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। यह ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि सामग्री तैयार करने वालों तथा ऑनलाइन पत्रकारों के बीच अंतर घटता जा रहा है।

जनवरी 2023 में सरकार न सोशल मीडिया "इन्फ्लुएंसर्स" के लिए अनिवार्य कर दिया था कि वे ब्रांड्स से मिलने वो भौतिक लाभों की घोषणा करे जैसे होटल में ठहरना आदि। मिलने वाले भौतिक लाभ घोषित करेंगे, होटल में ठहरने सहित। न्यूज़लाँड्री की कार्यकारी संपादक सुश्री मनीषा पांडे ने कहा, क्योंकि "यह किसी ब्रांड को प्रोत्साहित करने के समान है, केवल यहां ब्रांड सरकार है।"

हालांकि इन्फ्लुएंसर्स स्वयं को पूरी तरह पत्रकार न मानें लेकिन उनके द्वारा समाचार के नाम पर जो सामग्री परोसी जा रही है उसकी दर्शकों को ज्यादा पड़ताल करने की आवश्यकता है।

कुछ पत्रकारों को छोड़कर बाकी इन्फ्लुएंसर्स को पत्रकारिता का अनुभव नहीं है और ना ही वे प्रशिक्षित है।

सुश्री पांडे ने स्ट्रेट्स टाइम्स को कहा, "ये लोग हर चीज़ को केवल सामग्री के रूप में लिखते हैं और ज्यादा से ज्यादा दर्शक और विज्ञापन के पैसे के पीछे रहते हैं। राजनैतिक पार्टियों ने भी बहुत सावधानी से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से संपर्क साधा है जो उनके मत को मानते हैं और उनके नेताओं को ज्यादा से ज्यादा जनता के सामने आने का मौका देते हैं लेकिन मीडिया में प्रमुखता से आने वाले मुद्दों पर सवाल नहीं पूछते। सोशल मीडिया पर सक्रिय कई युवा पत्रकार के इंटरव्यू और जनसंपर्क के लिए ऑनलाइन लिखी गई सामग्री में फर्क ही नहीं समझते और इसे समझाना "जिम्मेवार मीडिया" का काम है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908